



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438]
No. 438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1983/अश्विन 8, 1905
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1983/ASHVINA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैकिंग प्रमाण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

का० अ० 702 (अ):—बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मूक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949 (1949 का 46) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक अधिसूचना, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे कि उक्त अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे, अर्थात् :—

राज्य :

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा

संघ शासित क्षेत्र :

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. चण्डीगढ़
4. दिल्ली

राज्य :

संघ शासित क्षेत्र :

6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू तथा कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र (जहां अधिनियम पहले से लागू है, राज्य के उस भाग के अलावा)
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. नागालैण्ड
15. राजस्थान
16. तमिलनाडु
17. त्रिपुरा
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल

[सं० एफ० 18/8/82-ओ० ओ०-1]

वी० के० सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—उड़ीसा में यह अधिनियम भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 278 पर प्रकाशित दिनांक 12 जुलाई, 1950 की अधिसूचना सं० सा० आ० 270 के अंतर्गत पहली अगस्त, 1950 से और पंजाब राज्य में भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 1597 पर प्रकाशित दिनांक 18 सितम्बर, 1951 की अधिसूचना संख्या सं० सा० आ० ० 1431 के अंतर्गत पहली अक्टूबर, 1951 से प्रवृत्त किया गया था।

इस अधिनियम के विस्तार को 1963 के विनियम 6, धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा संघ शासित क्षेत्र बादरा और नगर हुवेली तक और 1963 के विनियम 7, धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी तक बढ़ा कर वहाँ प्रवृत्त किया गया और इसके विस्तार को 1963 के विनियम 11, धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव और 1965 के विनियम 8, धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप मिनीकाय और अमीन-दीव द्वीप समूह तक बढ़ाया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1983

S.O. 702(E)—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949 (46 of 1949), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1983 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the following States and Union territories, namely:—

States	Union Territories
1. Andhra Pradesh	1. Andaman and Nicobar Islands
2. Assam	2. Arunachal Pradesh
3. Bihar	3. Chandigarh
4. Gujarat	4. Delhi
5. Haryana	

States

6. Himachal Pradesh
7. Jammu & Kashmir
8. Karnataka
9. Kerala
10. Madhya Pradesh
11. Maharashtra (except the Part of the State to which the Act is already in force)
12. Manipur
13. Meghalaya
14. Nagaland
15. Rajasthan
16. Tamil Nadu
17. Tripura
18. Uttar Pradesh
19. West Bengal

Union Territories

[No. F. 18/8/82-B.O.]

V. K. SIBAL, Joint Secy.

Note:—The Act was brought into force in Orissa on 1st August, 1950, vide Notification No. S.R.O. 270, dated the 12th July, 1950, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 278, and in the State of Punjab on the 1st October, 1951, vide Notification No. S.R.O. 1431, dated 18th September, 1951, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 1597.

The Act was extended to and brought into force in the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. 1 and Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. 1 and extended to Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch. and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch.